RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

INDORE 20 JANUARY TO 26 JANUARY 2021 प्रति बुधवार वर्ष 06 अंक 22 पृष्ठ 8 कीमत 5 रु.

Inside News

BPCL बीना रिफाइनरी में ओमान ऑयल की खरीदेगी हिस्सेदारी Page 2

ऐप फर्मों के वसूली एजेंटों पर सख्ती बरतेगा आरबीआई Page 5

मारुति सुजुकी ने जिम्नी का निर्यात शुरू किया Page 7

editoria!

घटे व्यापार घाटा

अर्थव्यवस्था को मंदी से निकाल कर गतिशील बनाने के लिए व्यापार घाटा कम करने की कोशिश जरूरी है. इसके लिए निर्यात बढ़ाने और आयात घटाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उचित ही कहा है कि उन आयातित वस्तुओं की पहचान की जानी चाहिए, जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है. उन्होंने औद्योगिक जगत का आह्वान किया है कि वे इस दिशा में शोध करें. दिसंबर में देश का व्यापार घाटा 25 महीनों में सबसे अधिक रहा है. कोरोना संकट के दौरान अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगा था. ऐसे में आयात, निर्यात या किसी भी आर्थिक गतिविधि में बड़ी उछाल या गिरावट स्वाभाविक है. लॉकडाउन के दौरान जून में तो आयात में बड़ी कमी के कारण व्यापार अधिशेष 18 सालों में पहली बार बढ़ गया था. आयात में हालिया बढ़ोतरी से यह इंगित होता है कि घरेलू मांग में वृद्धि हो रही है. अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने के अनेक सकारात्मक संकेतों में यह भी एक है, किंतु दीर्घकालिक आर्थिक व वित्तीय स्थायित्व की राह में आयात की अधिकता बड़ा अवरोध बन सकती है. इससे आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने में भी दिक्कत होगी. अधिक आयात से विदेशी मुद्रा भंडार भी प्रभावित होता है. जिन वस्तुओं को अन्य देशों से मंगाया जाता है, उनके घरेलू उत्पादन में कमी आ जाती है या फिर उन्हें देश में बनाने के लिए कोशिश नहीं की जाती है. कई चीजों के लिए भारत समेत अनेक देशों की चीन पर निर्भरता के प्रतिगामी परिणामों से सभी परिचित हैं. कुछ देश अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए शुल्कों में छूट जैसे उपायों से वस्तुओं के दाम कम कर देते हैं. इस वजह से घरेलू निर्माता उनसे प्रतिद्वंद्विता नहीं कर पाते और बाजार पर आयातित उत्पादों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है. कई आयातित उत्पाद या उनमें प्रयुक्त सामग्री पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी तात्कालिक तौर पर या कालांतर में खतरा बन सकते हैं. ऐसे कई क्षेत्र हैं, जिनमें निर्यात बढ़ाने की क्षमता देश में है. दिसंबर में तैयार कपड़ों और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में बड़ी कमी आयी है. सबसे अधिक आयातित वस्तुओं में वनस्पति तेल, इस्पात, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल हैं. इन वस्तुओं पर अगर अधिक ध्यान दिया जाए, तो इनका निर्यात भी हो सकेगा और घरेलू बाजार की मांग भी पूरी की जा सकेगी. जैसा कि गडकरी ने रेखांकित किया है, देश के भीतर बने सामानों की कीमत कुछ समय के लिए अधिक हो सकती है, लेकिन उनका उत्पादन बड़े पैमाने पर होने से बाद में दाम कम हो जायेंगे. हमारे देश में ही बड़ा बाजार मौजूद है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार इस बात पर जोर दिया है कि हमें स्थानीय उत्पादों को अपनाना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए. यदि अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद भारत बना सकता है, तो दुनिया भी उन्हें इस्तेमाल करेगी. ऐसा कर हम व्यापार घाटा कम कर आत्मनिर्भर हो सकेंगे.

मोदी सरकार आज करेगी फैसला

कर्मचारियों की छुट्टियां बढ़कर हो सकती हैं 300 और बदल सकते हैं पीएफ के नियम

नई दिल्ली। एजेंसी

नए श्रम कानूनों को लेकर एक बार फिर श्रम मंत्रालय, उद्योगजगत के प्रतिनिधि और लेबर यूनियन से जुड़े लोग आमने सामने बैठकर बातचीत करेंगे। हिन्दुस्तान को मिली जानकारी के मुताबिक हितधारकों के बीच बुधवार को होने वाली बैठक में संभवतः आखिरी दौर की बातचीत होगी।

पीएफ और अवकाश की सीमा पर होगा फैसला

जानकारी के मुताबिक इस बैठक में लेबर यूनियनों की तरफ से? उठाई गई पीएफ और अर्जित अवकाश की सीमा बढ़ाने की मांग पर भी फैसला लिया जाना है। भारतीय मजदूर संघ ने सरकार से मांग की है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के समरूप कर्मचारी भविष्य निधि योजना यानी ईपीएफ के तहत पात्रता मानदंड 15,000 रुपये मासिक वेतन से बढ़ाकर

21,000 रुपये किया जाए। वहीं यूनियन से जुड़े लोग चाहते हैं अर्जित अवकाश की सीमा 240 से बढ़ाकर 300 दिन कर दी जाए। सरकार से भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों, पत्रकारों और श्रव्य दृश्य श्रमिकों के साथ साथ सिनेमा क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लिए अलग नियम बनाए जाने की मांग की गई है।

1 अप्रैल से लागू होने है नए श्रम कानून

संसद से श्रम सुधारों से जुड़े नए कानून सितंबर 2020 में पास हुए थे। अब केंद्र सरकार की कोशिश है कि इन्हें इस साल अप्रैल से पहले यानि मौजूदा वित्तवर्ष में ही लागू कर दिया जाए। केंद्र सरकार की तरफ से इस बारे मे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी हितधारकों के साथ बैठक की गई जिसका कई लेबर यूनियनों की तरफ से बहिष्कार भी किया गया है। यही वजह है कि 20 जनवरी को होने वाली मीटिंग आमने सामने बैठक हो सकती है। मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक इन कानूनों पर ये अंतिम दौर की चर्चा होगी। सभी मुद्दों का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी और इसके बाद जल्द ही नियमों को नोटिफाई कर दिया जाएगा।

मांग को लेकर आशंका दूर होने से बढ़ीं तेल की कीमतें

सिंगापुर। एजेंसी

मंगलवार को तेल की कीमतें इस आशावाद में बढ़ी कि सरकारी प्रोत्साहन से वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ेगी और कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर दोबारा हुए लॉकडाउन से तेल की मांग पर असर को लेकर चिंता भी दूर हो जाएगी। मार्च का ब्रेंट क्रूड फ्यूचर 55 सेंट यानी 1 फीसदी चढ़कर 55.30 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया जबकि एक कारोबारी सत्र पहले यह 35 सेंट फिसल गया था। अमेरिका में वेस्ट टैक्सस इंटरमीडिएट क्रूड 16 सेंट चढ़कर 52.52 डॉलर प्रति बैरल पर रहा। सार्वजनिक अवकाश के कारण सोमवार को अमेरिकी बाजारों में सेटलमेंट नहीं हुआ। फरवरी का डब्ल्यूटीआई फ्यूचर बुधवार को एक्सपायर हो रहा है। दुनिया में कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातक चीन में मांग को लेकर निवेशक उत्साहित हैं। सोमवार को जारी आंकड़ों से पता चला है कि रिफाइनरी का उत्पादन 3 फीसदी बढ़कर साल 2020 में नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया। चीन एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था रही, जहां पिछले साल गिरावट नहीं आई क्योंकि कई देश कोविड महामारी पर लगाम कसने की चुनौती का सामना कर रहे थे। सिडनी में सीएमसी मार्केट्स के मुख्य रणनीतिकार माइकल मैकार्थी ने कहा, सोमवार को चीन में जारी आंकड़े तेल की कीमतों के लिए सकारात्मक रहे। निवेशकों की नजर अब बुधवार को अमेरिका के नए राष्ट्रपति की तरफ से दिए जाने वाले भाषण पर है, जहां देश के 1.9 लाख करोड़ डॉलर वाले पैकेज पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तेल की कीमतों को सऊदी अरब की तरफ से अगले दो महीने में होने वाली तेल की अतिरिक्त आपूर्ति में कटौती से सहारा मिला है, जिससे पहली तिमाही में वैश्विक तेल इन्वेंट्री 11 लाख बैरल रोजाना की कमी आ सकती है। एएनजेड के विश्लेषकों ने यह जानकारी दी। वैश्विक स्तर पर कोविड के बढ़ते मामले और फिर से हो रहे लॉकडाउन का तेल की मांग पर असर पड़ा और इससे कीमतें नहीं बढ़ पाईं। एएनजेड के विश्लेषकों ने जनवरी से दिसंबर में तेल की बिक्री में गिरावट को लेकर चिंता दूर की और चीन व जापान में कोविड के मामलों को लेकर भी, जिसका असर तेल की मांग पर पड़ सकता था। बैंक ने कहा कि यूरोप व अमेरिका में वैक्सीन लगाने के काम में सुस्ती भी इस बात की चिंता बढ़ा रही है कि तेल की मांग में सुधार को लेकर मुश्किल बना रहेगा।

भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को दो हार्बर क्रेन की आपूर्ति की

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत ने सोमवार को कहा कि उसने 2.5 करोड़ डॉलर से अधिक के एक सौदे में ईरान के चाबहार बंदरगाह को दो मोबाइल हार्बर क्रेन (एमएचसी) की आपूर्ति की है। इस कदम से बंदरगाह को बिना बाधा के माल चढ़ाने-उतारने में मदद मिलेगी। बंरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को दो एमएचसी की आपूर्ति की है। यह खेप 6 मोबाइल हार्बर क्रेन (एमएचसी) की आपूर्ति के लिए किये गये एक अनुबंध समझौते के तहत भेजी गयी है।'' इटली के मारघेरा बंदरगाह से पहुंची क्रेनों की इस खेप को 18 जनवरी 2021 को चाबहार बंदरगाह पर सफलतापूर्वक उतार लिया गया और अभी इन क्रेनों का परीक्षण चल रहा है। बयान में कहा गया कि 140 मीट्रिक टन भार उठाने की क्षमता से लैस मोबाइल हार्बर क्रेन (एमएचसी) जैसे बहुउद्देशीय उपकरण और सामान भारत पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) को चाबहार के शाहिद बेहेश्टी बंदरगाह में कंटेनर, बल्क और जनरल कार्गो की निर्बाध सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनायेंगे। यह चाबहार के शहीद बेहेश्टी बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के विकास में भारत की प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम है।

BPCL बीना रिफाइनरी में ओमान ऑयल की खरीदेगी हिस्सेदारी

2000 करोड़ रुपए की होगी डील

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने मध्य प्रदेश स्थित बीना रिफाइनरी परियोजना में ओमान ऑयल कंपनी QQ की हिस्सेदारी को आपसी सहमति के आधार पर खरीदने की मंजूरी पिछले महीने दे दी थी। एक खबर के मुताबिक, यह डील 1900 2000 करोड़ रुपए में हो सकती है। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि BPCL के निजीकरण से पहले यह डील हो सकती है। सरकार एक तरफ ँइण्थ में अपनी हिस्सेदारी बेचकर फंड जुटाने की तैयारी में है। दूसरी तरफ BPCL रणनीतिक डील कर रही है।

बीपीसीएल के पास भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड (बीओआरएल) में 63.68 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो मध्य प्रदेश के बीना में 78 लाख टन क्षमता वाली तेल रिफाइनरी का परिचालन करती है। कंपनी ने बताया कि बोर्ड ने भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड में ओक्यू एसएओसी (पूर्व नाम ओमान ऑयल कंपनी) से 88.86 करोड़ इक्विटी शेयर (39.62 प्रतिशत) हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी।

डील से BPCL की बढ़ सकती है वैल्यूएशन

BPCL की योजना बीना रिफाइनरी को मिलाने की है। बिना रिफाइनरी को भारत ओमान रिफाइनरी (BORL) के नाम से जाना जाता है। उम्मीद की जा रही है कि इस डील ने BPCL की वैल्यूएशन बढ़ सकती है और सरकार को अपनी हिस्सेदारी के बदले ज्यादा फंड मिल सकता है। इसके साथ ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बेचने में टैक्स एडवांटेज भी मिलेगा।

BPCL की बढ़ेगी हिस्सेदारा

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस डील के बाद शेयरहोल्डिंग पैटर्न बदल जाएगा। डिबेंचर और वारंट्स को जोड़ लें तो BORLमें BPCL की हिस्सेदारी बढ़कर 78 फीसदी हो जाएगी और QQ की हिस्सेदारी घटकर 22 फीसदी रह जाएगी।खबर के अनुसार, BPCL ने BORL को 1254.10 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था और 935.68 करोड़ रुपए का वारंट लिया था। BPCL ने 1000 करोड़ रुपए के ज़ीरो पर्सेंट कंप्लसरी कंवर्टिबल डिबेंचर भी सब्सक्राइब किया था। BPCL के बोर्ड ने बीना रिफाइनरी में QQ की हिस्सेदारी लेने का फैसला दिसंबर में किया था।

अमेरिका में राहत पैकेज की उम्मीद में कच्चा तेल चढ़ा, मांग बढ़ने की संभावना

नई दिल्ली। एजेंसी

बुधवार के कारोबार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का रुख देखा गया है। माना जा रहा है कि अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद अमेरिकी प्रशासन बड़े राहत पैकेज की घोषणा कर सकता है। अमेरिका की नई वित्त मंत्री जेनेट येलेन इस बात का पहले ही संकेत दे चुकी हैं। अगर ऐसा होता है तो ईंधन की मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अमेरिकी पश्चिम टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड वायदा बुधवार को 23 सेंट यानी 0.4 फीसदी चढ़कर 53.21 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि मंगलवार को इसमें 1.2 फीसदी की तेजी आई थी। इसी तरह से आज ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 25 सेंट या 0.5 फीसदी बढ़कर 56.15 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। मंगलवार को ब्रेंट क्रूड के दाम 2.1 फीसदी चढ़े थे। वहीं घरेलू वायदा बाजार में, सुबह 11.30 बजे के आसपास एमसीएक्स पर कच्चे तेल का फरवरी वायदा 31 रुपये यानी 0.80 फीसदी की तेजी के साथ 3919 रुपये प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। अमेरिका की नई वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने मंगलवार को सांसदों से आग्रह किया कि वे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महामारी को काबू में करने के लिए सरकारी खर्च बढ़ाएं। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी है। बावजूद इसके कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने पहली तिमाही के लिए कच्चे तेल की मांग का अनुमान 5.80 लाख बैरल घटा दिया है। यूरोप में लॉकडाउन प्रतिबंधों के चलते कच्चे तेल की मांग में कमी का अनुमान है। उधर, जर्मनी ने मंगलवार को अधिकांश दुकानों और स्कूलों के लिए एक और दो सप्ताह के लिए बंद कर दिया। कारोबारियों की नजरें जारी होने वाले अमेरिकी पेट्रोलियम संस्थान के आंकड़ों पर है। शुक्रवार को अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन कच्चे तेल और उत्पाद के आंकड़े जारी करेगा।

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया सात पैसे मजबूत

मुंबई। एजेंसी

घरेलू शेयर बाजार के सकारात्मक रुख और अमेरिकी मुद्रा की कमजोरी के चलते रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार के दौरान सात पैसे मजबूत होकर 73.10 के स्तर पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 73.11 पर खुला और बढ़त के साथ 73.10 पर आ गया, जो पिछले बंद के मुकाबले सात पैसे की बढ़ोतरी दर्शाता है। रुपया मंगलवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 73.17 पर बंद हुआ था। इसबीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.14 प्रतिशत गिरकर 90.37 के स्तर पर आ गया। कारोबारी गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक के खुले बाजार के संचालन का इंतजार भी करेंगे। आरबीआई गुरुवार को 100 अरब रुपये का एकमुश्त ओएमओ आयोजित करेगा। कारोबारियों ने बताया कि निवेशकों का ध्यान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के उद्घाटन समारोह पर भी होगा।

रुपये में लगातार दूसरे दिन भी तेजी, डॉलर के मुकाबले 12 पैसे मजबूत हुआ

मुंबई। एजेंसी

रुपये में लगातार दूसरे दिन बुधवार को तेजी बनी रही। घरेलू शेयर बाजार में उछाल और अमेरिकी डालर के अन्य मुद्राओं के समक्ष नरम होने के बीच रुपया प्रति डालर 12 पैसे और सुधर कर 73.05 (अनंतिम) पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 73.11 पर खुला और दिन के कारोबार के दौरान 73.05 के ऊपरी स्तर तथा 73.14 के निचले स्तर तक भी गया। अंत में रुपये की विनिमय दर 73.05 पर टिकी। पिछले बंद भाव के मुकाबले रुपये में यह 12 पैसे की तेजी दर्शाता है। मंगलवार को रुपया 73.17 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं वाला डॉलर सूचकांक 0.07 प्रतिशत गिरकर 90.43 पर आ गया। यह डालर की कमजोरी का सूचक है। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशक पूंजी बाजार में शुद्ध लिवाल रहे और उन्होंने मंगलवार को शुद्ध रूप से 257.55 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.70 प्रतिशत बढ़कर 56.29 डालर प्रति बैरल पर था।

झारखंड में आ गया इंडियन ऑयल का 160 रुपये प्रति लीटर वाला पेट्रोल

धनबाद। एजेंसी

इंडियन ऑयल का XP 100 पेट्रोल झारखंड के बाजार में भी आ गया है। इसकी बिक्री फिलहाल धनबाद और रांची में की जा रही है। दोनों शहरों के पेट्रोल पंप पर यह पेट्रोल उपलब्ध है। हालांकि कीमत सामान्य पेट्रोल से दोगुना है-160 रुपये प्रतिलीटर। जाहिर है जब दाम दोगुना है तो इसकी खासियत भी खास होगी। इंडियन ऑयल का दावा है कि अगर आप अपनी कार और बाइक में डालते हैं तो ताकत बढ़ जाएगी। न सिर्फ माइलेज बढ़ेगा बल्कि ड्राइविंग का अंदाज ही बदल जाएगा। इंडियन ऑयल XP100 स्वदेशी तकनीक पर विकसित प्रीमियम पेट्रोल है। कीमत 160 रुपए प्रति लीटर है। यह पेट्रोल महंगा जरूर है। पर कार और बाइक में डालते हैं उसकी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। पूरे झारखंड में यह पेट्रोल केवल दो शहरों में ही लांच किया गया है-धनबाद और रांची। इस पेट्रोल की खासियत की बात करें तो इंडियन ऑयल रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा विकसित स्वदेशी ऑक्टा मैक्स तकनीक का उपयोग कर एक्सपी 100 प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल का उत्पादन किया है। ऑक्टेन की हाई रेटिंग नॉकिंग को रेजिस्टेंस देती है। जिसके कारण इंजन के भीतर गर्मी से इंधन स्वतः प्रज्वलित होता है। सुपर कार और परफॉर्मेंस बाइक पर हाई कंप्रेशन इंजन के साथ एक उच्च ऑक्टेन विशेष रूप से काम करता है।

इंडियनऑयल IndianOil | XP100 100 octane premium petrol

इस तरह के ईंधन का उपयोग अमेरिका और जर्मनी जैसे देश कर रहे हैं। ईंधन की गुणवत्ता के मामले में एक्सपी 100 एक बड़ा कदम है। यदि इसकी तुलना नियमित पेट्रोल से की जाए टॉप करीब 77 रुपए ज्यादा है। यह पेट्रोल का सबसे अच्छा ग्रेड है। वहीं धनबाद स्थित एक पेट्रोल पंप में जब लोगों ने देखा की 160 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है तो सभी भौचक्क रह गए। पहले तो लोगों को समझ में नहीं आया की यह चीज क्या है, और इसकी कीमत इतनी क्यों है। इंडियन आयल के उप महाप्रबंधक दीपक कुमार ने लोगों को बताया की यह सुपर प्रीमियम पैट्रोल है। जिसे बाइक और कार में डालने पर उसकी स्पीड और पावर बढ़ जाती है। यह झारखंड में केवल 2 जगहों पर ही मिल रहा है।

Budget 2021

एल्युमीनियम सेक्टर ने की सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की मांग, कोयले पर जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस खत्म करने की भी अपील

नई दिल्ली। एजेंसी

एल्युमीनियम उद्योग ने आगामी बजट में प्राइमरी एल्युमीनियम और एल्युमीनियम स्क्रैप पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 10 फीसद करने की मांग की है। एल्युमीनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएआइ) का कहना है कि बढ़ते आयात के कारण घरेलू एल्युमीनियम उद्योग संकट का सामना कर रहा है। आगामी बजट से पहले एएआइ ने सरकार के समक्ष अपने प्रजेंटेशन में कहा, 'इस चुनौतीपूर्ण दौर से निकलने के लिए भारतीय एल्युमीनियम उद्योग को सरकार से तत्काल सहयोग की जरूरत है। यह उद्योग बजट में अपने लिए समर्थन की उम्मीद कर रहा है।' उद्योग की ओर से सुझाव देते हुए एएआइ ने कहा कि प्राइमरी मेटल और एल्युमीनियम स्क्रैप पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10 फीसद करने की जरूरत है। साथ ही कोयले पर जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस खत्म करने का सुझाव भी दिया गया है। अभी कोयले पर 400 रुपया प्रति टन सेस लगता है। एल्युमीनियम उद्योग ने एल्युमीनियम फ्लोराइड और कोल तार जैसे अहम कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी घटाने की अपील भी की है। एएआइ ने कहा, 'बढ़ती उत्पादन एवं लॉजिस्टिक्स लागत के कारण उद्योग मुश्किल का सामना कर रहा है। कोरोना महामारी ने चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। महामारी के कारण घरेलू एल्युमीनियम की मांग और कम हो गई है। दूसरी ओर, केंद्र एवं राज्य के करों के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी भारतीय उद्योग अन्य वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के सामने नहीं टिक पाता है।'

बजट में एलटीसीजी रियायत, लाभांश कराधान पर स्पष्टता चाहता है बाजार

मुंबई। एजेंसी

पिछले वर्षों की तरह ही पूंजी बाजार कारोबारियों को इस साल भी बजट से कई उम्मीदें हैं। इनमें से कई मांगे काफी पुरानी हैं, जबकि कुछ पिछले साल प्रभावी बजटीय बदलावों से सामने आई हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने कुछ प्रमुख उद्योग प्रस्तावों और बदलावों पर विचार दिया है जिन पर सरकार इस साल के बजट से पहले ध्यान दे सकती है।

एलटीसीजी और एसटीटी

उद्योग कारोबारियों का मानना है कि सरकार

सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों की बिक्री से संबंधित दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) पर कर रियायत देगी। सरकार ऐसी छूट के लिए अवधि बढ़ाकर 24 महीने कर सकती है और यह व्यवस्था गैर-सूचीबद्ध शेयरों के समान बना सकती है। एफवाईईआरएस के सह-संस्थापक तेजस खोडे ने कहा, 'एलटीसीजीकर समाप्त करना एक स्वागत योग्य कदम होगा। चर्चा का मुख्य मुद्दा दीर्घावधि की अवधारणा को दो वर्ष के तौर पर पुनः परिभाषित करना और कराधान को शून्य करना है। इससे सभी वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश की अवधि के लिए स्थायित्व आ सकेगा।' प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) और ड्क्षजस लेनदेन कर (सीटीटी) में कटौती की मांग लंबे समय से की जाती रही है। एक कर परामर्श फर्म के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'यदि एलटीसीजी को बरकरार रखा जाता है तो एसटीटी को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए, क्योंकि एसटीटी को एलटीसीजी कर के लिए प्रतिस्थापन के तौर पर पेश किया गया था।'

यूलिप और एमएफ के बीच कर समानता

उद्योग कारोबारियों को उम्मीद है कि सरकार यूलिप और इक्विटी म्युचुअल फंडों के बीच कर समानता लाएगी, ये दोनों ही निवेश उत्पाद हैं और प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। मौजूदा समय में, यूलिप निवेशकों को निवेश से निकलने पर पूंजीगत लाभ कर चुकाने की जरूरत नहीं होती है। इसमें निवेश की निकासी पर एसटीटी नहीं लगता है और न ही बीमा कंपनियों के यलिप से निकासी पर आय कर लागू है। इस निकासी में समय पूर्व सरेंडर और आंशिक निकासी भी शामिल है।

म्युचुअल फंड

एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) ने 'एमएफ-लिंक्ड रिटायरमेंट प्लान' (एमएफएलआरपी) के तौर पर पेंशन प्लान पेश करने की राह आसान की है, जो आयकर, 1961 की धाराओं 80सीसीडी (1) और 80सीसीडी (1बी) के तहत कर लाभ के अधीन होगा। ऐसे प्लान के लिए कर लाभ गणना के लिए नियोक्ता और कर्मचारी के योगदानों की कुल रकम को शामिल किया जाना चाहिए। नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान को आयकर, 1961 की धारा 36(1)(4ए) के तहत 'बिजनेस एक्सपेंस' का पात्र होने की अनुमति दी जानी चाहिए। एम्फी एक म्युचुअल फंड प्लान/ऑप्शन से फंड हाउस की अन्य समान योजना में बदलाव को पूंजीगत लाभ कर से मुक्त रखना चाहता है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई)

सरकार उन कर नियमों की पुनः समीक्षा कर सकती है जो एफपीआई के लिए लाभांश पर विदहोल्डिंग टैक्स से संबंधित हैं। मौजूदा समय में, कंपनियां एफपीआई के लिए लाभांश भुगतान पर 20 प्रतिशत (सरचार्ज अतिरिक्त) और उपकर चुकाती हैं, भले ही वे उस क्षेत्र से निवेश करती हों जो उस देश के साथ भारत के डबल टैक्स अवॉयडेंस एग्रीमेंट (दोहरे कराधान से बचने के समझौते) पर आधारित कम दर मुहैया कराते हों। कम दर 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत या 15 प्रतिशत हो सकती है।

ब्रोकर

एसोसिएशन ऑफ नैशनल एक्सचेंजेज मेंबर्स ऑफ इंडिया (एएनएमआई) ने सरकार से ब्रोकिंग उद्योग के लिए जीएसटी दरें तर्कसंगत बनाए जाने का अनुरोध किया है। एएनएमआई ने संभावित आय की अवधारणा से दूर रहने और प्यावसायिक आय, दीर्घावधि पूंजी लाभ, और अल्पावधि पूंजी लाभ के लिए पूंजी बाजार लेनदेन से संबंधित आय वर्ग सीमित रखे जाने का भी अनुरोध किया है। अन्य पुरानी मांग कैटेगरी-3 एआईएफ के लिए पास-थ्रो स्टेटस को लेकर है, जैसा कि 2015 में कैटेगरी-1 और कैटेगरी-2 एआईएफ के लिए मुहैया कराया गया था।

कृषि सेक्टर को नई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रोत्साहन की है उम्मीद, जानें इंडस्ट्री लीडर्स की मांग

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के काल में जब दुनियाभर की इकोनॉमी चरमरा गई, उसी वक्त भारत में कृषि क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली। इससे इस बात को एक बार फिर से मजबूती मिली है कि भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। इसी वजह से सरकार भी देश को कृषि सेक्टर का सबसे बड़ा निर्यातक बनाने की दिशा में काम कर रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कृषि सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञ और कंपनियां बजट से किस तरह का आस लगाए बैठी हैं। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को आगामी केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

Aquaconnect के फाउंडर और सीईओ राजमनोहर सोमासुंदरम ने कहा है कि सरकार को भूमि को लीज पर देने के लिए एक सिंगल विंडो लीजिंग प्रोग्राम लाना चाहिए। इससे पढ़े-लिखे युवा आसानी से एक्वाकल्चर में प्रवेश कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को नई टेक्नोलॉजी को अपनाने पर जीएसटी सब्सिडी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी पर आधारित कृषि से ना सिर्फ किसान अपना उत्पादन बढ़ा पाएंगे बल्कि डेटा इंटेलिजेंस की मदद से पॉलिसीमेकर्स, रेगुलेटरी, बैंकर्स, इंश्योरेंस कंपनियां डेटा पर आधारित नीतियां तय कर पाएंगी।

उन्होंने मूल्य की गारंटी के लिए नया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाने का सुझाव दिया है।

एग्री फिनटेक Arya के को-फाउंडर और सीईओ प्रसन्न राव ने आगामी बजट में एग्री फिनटेक स्टार्टअप एनबीएफसी को पीएसएल में शामिल करने जैसे उपाय करने का सुझाव दिया है। ध्स्हम्न्दी के मैनेजिंग पार्टनर जिनेश शाह ने कहा कि कोविड-19 की वजह से पैदा हुए बाधाओं के निवारण में एग्रीटेक से काफी मदद मिली। मुश्किल भरे इस समय में सेक्टर को सरकार से काफी अधिक मदद मिली। वहीं, किसानों पर आधारित डीबीटी पहलों से ग्रामीण इकोनॉमी में लचिलता विकसित करने में काफी मदद मिली। उन्होंने कहा कि आगामी बजट में इसी तरह के कदम उठाए जाने की उम्मीद की है जिससे आने वाले समय में कृषि सेक्टर में मोमेंटम बना रहा सकता है।

वैश्विक आरएंडडी सेवा बाजार के 50 प्रतिशत हिस्से पर नजर के साथ भारत का 'आत्मनिर्भर भारत' पर जोर

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार और वाणिज्य विभाग ने फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस से 'देश से आरएंडडी सेवा निर्यात को संवर्धन' पर पहली राउंडटेबल के आयोजन की पहल की है। राउंडटेबल में 180 से ज्यादा वैज्ञानिकों, सरकारी निजी अनुसंधान संगठनों ने भाग लिया था। इस अवसर पर वाणिज्य विभाग, आर्थिक मामलों के विभाग, विदेश मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, दूरसंचार विभाग, एमईआईटीवाई, सीएसआईआर, आईसीएमआर, व्यापार, शिक्षा क्षेत्र, स्टार्टअप सदस्यों और अनुभवी निर्यातकों और कई अन्य सरकारी व निजी संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

राउंडटेबल को संबोधित करते हुए फियो के अध्यक्ष श्री शरद कुमार सराफ ने सरकार के आरएंडडी सेक्टर में निवेश दोगुना से ज्यादा बढ़ाकर जीडीपी का लगभग 2 प्रतिशत करने के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे आरएंडडी सेवा क्षेत्र को आगे बढ़ने और आने वाले वर्षों में अपना

निर्यात दोगुना करने में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने राज्य सरकारों से भी आरएडंडी सेवा क्षेत्र में ज्यादा भागीदारी और सहयोग बढ़ाने के लिए आगे आने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, वर्तमान में यह केंद्र सरकार के लिए आरएंडडी सेवा निर्यात को प्रोत्साहन देने की दिशा में अहम कार्य है। श्री सराफ ने सरकार से एसईआईएस जैसी योजनाओं के माध्यम से, देश में सही बुनियादी ढांचा और इकोसिस्टम तैयार करके, सही नियामकीय व्यवस्था उपलब्ध कराकर, कर व्यवस्था को व्यवस्थित करके, सेक्टर को प्रोत्साहन देकर और विकास सुनिश्चित करके व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक समान अवसर उपलब्ध कराकर आरएंडडी सेवा निर्यात को बढ़ावा देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उच्च तकनीक निर्यात पर ज्यादा ध्यान देकर भारत के निर्यात की स्थिति बदलने के लिए आरएंडडी खासा अहम है।

भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के विजय राघवन ने मुख्य संबोधन देते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी से भविष्य के लिए कई सबक मिले हैं। एक प्रमुख सबक यह है कि देशों को ऐसे संकट से बचने के क्रम में आरएंडडी में अपना निवेश बढ़ाने की जरूरत है। वैश्विक भागीदारी और समन्वय के माध्यम से भी आरएंडडी में निवेश किए जाने की जरूरत है। दुनिया भर में आरएंडडी सेवाओं के आदान प्रदान के महत्व को कम आंका गया है। आज आरएंडडी निर्यात का महत्व खासा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक नीति निर्माताओं का ध्यान उच्च तकनीक आधारित वाणिज्यिक निर्यात पर रहा है, क्योंकि उच्च तकनीक निर्यात (एचटीएक्स) से एक देश के जुड़ाव से उसकी अर्थव्यवस्था, उत्पादकता के स्तर पर बदलाव और भावी क्षमताओं के बारे में पता चलता है। सरकार सेवा क्षेत्र के विकास में तेजी और आरएंडडी सेक्टर में उसके निर्यात में बढ़ोतरी की जरूरत को समझती है। भारत का वैज्ञानिक कार्यबल वैश्विक स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और वे पहले ही वैश्विक आरएंडडी सेक्टर में एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। वहीं, विकसित देश इस तथ्य को स्वीकार करते हैं और भारतीय प्रतिभा व उनकी तकनीक विशेषज्ञता को सम्मान देते हैं। प्रोफेसर विजय राघवन ने कहा कि वैश्विक बाजार में आरएंडडी क्षेत्र के लिए एक प्रकार के ब्रांड के रूप में भारत पहले ही स्थापित हो चुका है।

उन्होंने कहा कि हमें सेक्टर में ज्यादा एफडीआई प्रवाह, ज्यादा उपक्रमों के सामने आने और उनके द्वारा देश में आरएंडडी सुविधाओं की स्थापना की जरूरत है। भारत ने आने वाले साल में 50 करोड़ डॉलर का एफडीआई निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य तय किया है। आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में 'आत्मनिर्भर' भारत मिशन काफी अहम है। प्रो. के विजय राघवन ने फियो द्वारा अपने मोबाइल ऐप निर्यात मित्र के माध्यम से दी गईं आरएंडडी सेवाओं से मिले व्यावसायिक अवसरों पर प्रकाश डाला है, जिसमें वैश्विक तकनीक अनुरोध, तकनीक पेशकश और साथ ही वैश्विक आरएंडडी भागीदारी के अवसरों को शामिल किया गया है। वैज्ञानिक सचिव डॉ. अरबिंद मित्रा; वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव श्री विद्युत बिहारी स्वैन; फियो के डीजी एवं सीईओ डॉ. अजय सहाय, नैस्कॉम से श्री शिव प्रसाद और अन्य ने भी भारत से आरएंडडी सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन दिए जाने पर अपने विचार साझा किए। फिलिप्स इंडिया लि., डेकी इलेक्ट्रॉनिक्स लि., सीमेंस लि., सायंट लि., रॉबर्ट बॉश इंजीनियरिंग एंड बिजनेस सॉल्युशंस लि., इलेक्ट्रॉ ईवी, जनरल इलेक्ट्रिक इंडिया, लैंडिसगिर से जुड़े प्रमुख उद्योगपतियों ने देश से आरएंडडी सेवाओं के निर्यात में उनके सामने आने वाली चुनौतियां साझा कीं। इस अवसर पर भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के विजय राघवन ने आरएंडडी सेवा निर्यात ई-कॉमर्स पोर्टल का एक प्रोटोटाइप लॉन्च किया, जिससे इच्छुक भारतीय कंपनियां पोर्टल पर अपना ई-स्टोर तैयार करने, वैश्विक बाजार में कदम रखने और कारोबारी लेनदेन करने में भी सक्षम हो जाएंगी। आरएंडडी सेवा निर्यातकों को प्रोत्साहन देने और मान्यता देने के क्रम में प्रो. के विजय राघवन ने सेक्टर के लिए फियो के साथ मिलकर 2021-22 से राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत करने की भी घोषणा की।

रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ बाजार

सेंसेक्स 393 अंक चढ़कर और 14, 600 के पार निपटा निफ्टी

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

शेयर बाजार में बुधवार दिनभर बढ़त का सिलसिला जारी रहा। बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई थी और बलरन दिनभर जारी रहा। दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद सेंसेक्स हरे निशान पर बंद हुआ। दोपहर बाद बाजार में खरीदारी बढ़ी. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 393.83 अंक यानी 0.80 फीसदी की जोरदार बढ़त

के साथ 49, 792.12 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 123.55 अंक यानी 0.85 फीसदी की बढ़त के साथ 14, 644.70 के स्तर पर बंद हुआ. यह सेंसेक्स-निफ्टी का अभी तक का उच्चतम स्तर है। अमेरिका में ताजा प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीद से वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी आई, जिसका असर घरेलू बाजार पर देखा गया। चौतरफा खरीदारी की वजह से सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 197 लाख करोड़ रुपये के पार चला गया। पिछले हफ्ते बीएसई-30 शेयरों वाला सेंसेक्स 252.16 अंक यानी 0.51 फीसदी लाभ में था। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 86.45 अंक यानी 0.60 फीसदी चढ़ गया। आम बजट से पहले निवेशक काफी चिंतित हैं, क्योंकि ज्यादातर जानकारों के मुताबिक, कोरोना की वजह से इस बार का बजट उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा। इसलिए बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। दिग्गज शेयरों में, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, मारुति, विप्रो और अडाणी पोर्ट्स के शेयर बढ़कर बंद हुए. वहीं पावर ग्रिड, श्री सीमेंट, एनटीपीसी, गेल और एचडीएफसी बैंक के शेयर गिरकर बंद हुए।

प्रधान ने हजीरा में शेल इंडिया की एलएनजी ट्रक लदान इकाई का उद्घाटन किया

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को गुजरात के हजीरा में शेल इंडिया के तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की ट्रक-लदान इकाई का उद्घाटन किया। इसके साथ ही शेल इंडिया की देश में एलएनजी आपूर्ति परिचालन की शुरुआत हो गई। पेट्रोलियम मंत्रालय की जारी विज्ञप्ति के मुताबिक इस अवसर पर प्रधान ने कहा कि यह इकाई ग्रिड क्षेत्रों के बाहर ऐसी जगहों पर प्राकृतिक गैस की उपलब्धता को बढ़ावा देगी जहां कोई गैस पाइपलाइन नहीं है। उन्होंने कहा कि यह लंबी दूरी की यात्रा तय करने वाले ट्रकों में एलएनजी के इस्तेमाल को भी प्रोत्साहित करेगी। प्रधान ने मंगलवार की गई इस महत्वपूर्ण पहल के लिए शेल इंडिया की टीम की सराहना करते हुए कहा कि एलएनजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से नए बाजारों के उभरने में मदद मिलेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, उद्योगों के लिए स्वच्छ ईंधन सुनिश्चित होगा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में एक और बड़ा कदम है। 'हम अपने अपने उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों में स्वच्छ ऊर्जा की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था गैस आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील हो सके, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों का समाधान किया जा सके और एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो सके।' शेल एनर्जी इंडिया द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि औद्योगिक क्षेत्र स्थित गैस ग्राहक इसके प्राथमिक लाभार्थी होंगे। इसके साथ ही लघु आकार एलएनजी से बाजार को बढ़ावा मिलेगा और जिन क्षेत्रों में हाल में ही शहरी गैस वितरण के लिये लाइसेंस दिया गया है और जो पाइपलाइन से नहीं जुड़े हैं इससे उन्हें भी इससे समर्थन प्राप्त होगा। शेल एनर्जी इंडिया का गुजरात के हजीरा (सूरत) में सालाना 50 लाख टन क्षमता का एलएनजी आयात टर्मिनल है। यह टर्मिनल 2005 से काम कर रहा है और अब तक यहां 600 एलएनजी कार्गो पहुंच चुके हैं।

मंत्रिमंडल ने उज्बेकिस्तान के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू को मंजूरी दी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र (एमओयू) को मंजूरी दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी।" बयान के अनुसार एमओयू के तहत मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान और उज्बेकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (आईएसईआई) के बीच शोध, प्रदर्शन, पायलट परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। आपसी सहयोग के लिए जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है, उनमें सौर फोटोवोल्टिक, भंडारण तकनीक और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल हैं।

ऐप फर्मों के वसूली एजेंटों पर सख्ती बरतेगा आरबीआई

मुंबई। एजेंसी

ऐप के जरिये कर्ज देने वाली फर्मों का अध्ययन करने के लिए गठित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की कार्य समिति वसूली एजेंटों की ज्यादतियों, खास तौर पर छोटी रकम के देर से भुगतान के लिए ग्राहकों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयासों को रोकने के उपायों के बारे में सुझाव दे सकती है।

आरबीआई के जानकार सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय बैंक की राय है कि डिफॉल्टरों या देर से भुगतान करने वालों की छवि खराब करने के मकसद से संपर्क सूची में शामिल लोगों को वसूली एजेंट द्वारा टेक्स्ट संदेश भेजने के लिए निजी मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करने से रोकने के तत्काल उपाय होने चाहिए।

ऐप के जरिये कर्ज देने वाली फर्में जरूरतमंदों को कुछेक सौ या कुछ हजार रुपये तक का कर्ज देती हैं लेकिन उस पर ऊंची दरों पर ब्याज वसूला जाता है। कर्ज लेने वाला अगर भुगतान में देरी करता है तो ऋणदाता का टेली-कॉलर संबंधित ग्राहक के संपर्क सूची में शामिल सभी लोगों या परिवार के सदस्यों को लगातार संदेश भेजना शुरू कर देता है। कई बार आधार और स्थायी खाता संख्या (पैन) जैसे संवेदनशील जानकारियां भी स्कैन करके भेज दी जाती हैं।

जब यह ऐप डाउनलोड किया जाता है तो वसूली एजेंटों के पास संबंधित व्यक्ति के संपर्कों की पूरी सूची आ जाती है। इसका इस्तेमाल वे बाद में कर्जदारों को धमकाने में कर सकते हैं। इस तरह के ऐप को जब इन्स्टॉल किया जाता है तो संपर्क सूची, गैलरी और मैसेज तक पहुंचने की अनुमति देने के लिए कहा जाता है। अनुमति मिलने के बाद कर्जदाता के पास संबंधित व्यक्ति के फोन की सारी जानकारी उपलब्ध हो जाती है।

चाइनीज ऐप के तौर पर जाने जाने वाले कर्ज देने वाले ऐसे ऐप के मामले में यह बात सही साबित होती है। ग्राहकों और सरकारी एजेंसियों से शिकायत मिलने के बाद इनमें से कई ऐप को गूगल ने पिछले हफ्ते प्ले स्टोर से हटा दिया था। इस तरह की शिकायतों को देखने वाले सूत्रों का कहना है कि इस तरह की कार्यप्रणाली केवल चाइनीज ऐप द्वारा ही नहीं अपनाई जाती है बल्कि कुछ विनियमित फर्में भी ऐसा ही करती हैं। अक्सर दोनों तरह की फर्मों के लिए वसूली एजेंट समान होते हैं।

फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर इम्पावरमेंट (फेस) के संस्थापक सदस्य और अर्लीसैलरी के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्याधिकारी अक्षय मेहरोत्रा ने कहा, 'विनियमित डिजिटल ऋणदाताओं को वीडियो केवाई के लिए लोकेशन एक्सेस की जरूरत होती है। इसके लिए जीपीएस लोकेशन का उपयोग किया जाता है।' मेहरोत्रा ने कहा, 'विनियमित इकाइयों के पास ब्यूरो डेटा की पहुंच होती है, जिसका मतलब है कि उनकी ग्राहक के वैकल्पिक मोबाइल नंबरों तक पहुंच होती है। लेकिन गैर-विनियमित इकाइयों के पास ब्यूरो की पहुंच नहीं होती है, ऐसे में वे ग्राहकों के कॉन्टैक्ट बुक और फोटो गैलरी तक पहुंच बनाते हैं।' अधिकांश विनियमित इकाइयां कॉन्टैक्ट बुक और फोटो गैलरी तक पहुंच नहीं चाहती हैं। किसी भी तरह की विशिष्ट अनुमति के लिए वे नियामकीय प्रारूप के अंतर्गत अनुमति मांगते हैं। इसमें ग्राहक पता कर सकते हैं कि क्यों और किस तरह की जानकारी ली जा रही है। मेहरोत्रा ने कहा, 'वे अनुमति देने या उससे इनकार कर सकते हैं। इसमें दो बार सहमति देनी होती है, एक बार हमें और एक बार गूगल ऐंड्रॉयड पॉप-अप पर।' ऐप के जरिये कर्ज देने वाली फर्मों के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार कुछ ऐप को ग्राहकों की गैलरी और संपर्क सूची तक पहुंच की जरूरत होती है। उनका दावा है कि वे संपर्क सूची की पहुंच का उपयोग अंडरराइटिंग नियमों को पूरा करने के लिए करते हैं और गैलरी के जरिये कर्ज लेने वालों की वास्तविकता का आकलन किया जाता है। क्रेडिटबी के मुख्य कार्याधिकारी और फेस के सह-संस्थापक मधुसूदन एकामबरम ने कहा, 'यह पूरी तरह से अनुचित है। कई ऐप न केवल उपयोगकर्ता से उनकी संपर्क सूची की पहुंच मांगते हैं, बल्कि उसे टेली-कॉलिंग वसूली एजेंट को भी मुहैया कराते हैं, जो ग्राहकों का उत्पीडन करते हैं।'उन्होंने कहा कि नियामक द्वारा इस दिशा में सख्ती बरतने की उम्मीद है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने और दिशानिर्देश बनाए जाने की उम्मीद है। इससे कुछ फर्में अलग-अलग नाम से बाजार में वापस नहीं लौट पाएंगी।

लॉकडाउन के दौरान ऐसे ऐप की बाढ़ आ गई और कर्जदारों का उत्पीड? भी बढ़ गया। इसी शिकायतों को देखते हुए आरबीआई ने कार्य समिति बनाई है। सूत्रों ने बताया कि समिति की पहली बैठक इसी हफ्ते होगी। ऐप के जरिये कर्ज देने वाली फर्मों के लिए नियम बदले जाने की उम्मीद है।

इससे पहले 2010 में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाना को लेकर शिकायतें मिलने के बाद आरबीआई ने नियमों को सख्त किया था। वसूली एजेंट के मामले में नियमों का पालन नहीं करने वाली एनबीएफसी पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि नियामक भविष्य में गूगल और ऐपल से ऐसे ऐप को संपर्कों, संदेश और ईमेल की पहुंच देने से इनकार करने की मांग करेगा।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 75.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 586.082 अरब डॉलर की रेकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

देश का विदेशी मुद्रा भंडार आठ जनवरी को समाप्त सप्ताह में 75.8 करोड़ डॉलर बढ़ कर 586.082 अरब डॉलर की सर्वोच्च ऊंचाई को छू गया। रिजर्व बैंक के शुक्रवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इससे पहले एक जनवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 4.483 अरब डॉलर बढ़कर 585.324 अरब डॉलर की ऊंचाई को छू गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार रिव्यू की अवधि में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (एफसीए) के बढ़ने की वजह से मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। विदेशीमुद्रा परिसंपत्तियां, कुल विदेशी मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा होती है। रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन अवधि में एफसीए 15 करोड़ डॉलर बढ़कर 541.791 अरब डॉलर हो गया। एफसीए को दर्शाया डॉलर में जाता है, लेकिन इसमें यूरो, पौंड और येन जैसी अन्य विदेशी मुद्राएं भी शामिल होती है। आंकड़ों के अनुसार 25 दिसंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान देश का स्वर्ण भंडार मूल्य 56.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 37.594 अरब डॉलर हो गया। देश को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में मिला विशेष आहरण अधिकार पिछले सप्ताह अपरिवर्तित रहने के बाद 50 लाख डॉलर बढ़कर 1.515 अरब डॉलर हो गया जबकि आईएमएफ के पास आरक्षित मुद्रा भंडार 3.5 करोड़ डॉलर बढ़कर 5.181 अरब डॉलर हो गया।

क्या है लद्दाख का आइस स्तूप प्रोजेक्ट, जिसके लिए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को मिला यह प्रतिष्ठित पुरस्कार

नई दिल्ली। एजेंसी

कोल्ड डेजर्ट (Cold Dessert) में भी पानी की किल्लत (Water Scarcity) दूर हो, इसके लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय (Tribal Affairs Ministry) ने लद्दाख के गांव-गांव में आइस स्तूप (Ice Stupas) या बर्फ के स्तूप बनाने का प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। इस परियोजना के तहत हर साल 25 नए आइस स्तूप बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हर आइस स्तूप में 25 से 30 लाख लीटर पानी स्टोर किया जा सकता है। इसी की सफलता ने इस साल मिनिस्ट्री आफ ट्राइबल अफेयर्स को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार दिलवाया। कल ही केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस परियोजना के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड ग्रहण किया।

लद्दाख भारत के चरम उत्तर में एक हिमालयी पर्वतीय रेगिस्तान है, जिसमें 2,700 मीटर से लेकर 4,000 मी ऊंचाई तक स्थित गांव हैं। वहां सर्दियों के तापमान माइनस 30 डिग्री हो जाता है। इतनी सर्दी होते हुए भी वहां साल में महज 100 मिमी की औसत बारिश होती है। इसलिए वहां मानव बस्तियां हमेशा से हिमनद धाराओं (glacial streams) के आसपास स्थित होती हैं। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग (Global Warming) का असर से लद्दाख भी अछूता नहीं है। इसलिए वहां पानी की भीषण तंगी हो रही है। जब खेती नहीं होगी तो दूर-दराज के गांवों में रहने का क्या फायदा, इसलिए वहां गांवों से लोग पलायन कर रहे हैं और गांव वीरान हो रहे हैं। इसके समाधान के रूप में आया आइस स्तूप (Ice Stupa)।

लद्दाख के ज्यादातर गांवों को पानी की कमी (Water Scarcity) का सामना करना पड़ता है। खास कर अप्रैल और मई के दो महीनों के दौरान जब नदियों में थोड़ा पानी ही रह जाता है। इस समय नई लगाई गई फसलों (New Crops) की सिंचाई करनी पड़ती है। यदि पानी नहीं हो तो फसल चौपट। फिर गांव में रह कर क्या करना। इसलिए लोग पलायन कर जाते हैं। वहां जून के मध्य तक पहाड़ों में बर्फ और ग्लेशियरों (Glaciar) के तेजी से पिघलने के कारण पानी की अधिकता होती है और यहां तक कि बाढ़ भी आती है। वहां सितंबर तक सभी खेती की गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं।

लद्दाखी गांवों के लिए अप्रैल और मई का महीना ही पानी के बिना काटना मुश्किल हो जाता है। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय की प्रवक्ता के मुताबिक उन ट्राइबल बस्तियों में लोग रहे, इसके लिए जरूरी था पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसलिए गांव में एक स्ट्रेटेजिक प्लेस पर स्तूप के आकार में बर्फ जमा करने की परियोजना शुरू की गई। इस स्तूप में उतना बर्फ जमा हो सकता है, जिससे 25 से 30 लाख लीटर पानी मिल सके। इसका उपयोग उन्हीं दो महीनों के दौरान पेय जल, घर के दैनंदिन कामकाज करने और खेती-बाड़ी में होता है। इससे पेड़-पौधों की भी सिंचाई होती है।

मंत्रालय ने क्या निकाला समाधान

मंत्रालय (Tribal Affairs ministry) ने दि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स (The Himalayan Institute of Alternatives, Ladakh(HIAL)), लद्दाख की और कुछ स्थानीय लोगों की सहायता से वहां बड़े पैमाने पर आइस स्तूप बनाने की योजना बनाई। इस पर नवंबर 2019 से काम हुआ और वर्ष 2019-20 के दौरान 26 आइस स्तूप बना दिए गए। इससे छह करोड लीटर से भी ज्यादा पानी के स्टोरेज का इंतजाम हो गया। इस साल भी कम से कम 25 आइस स्तूप बनाने हैं। मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल जितने स्तूप बने थे, वह तो इस साल बनेंगे ही, इस साल अतिक्त 25 स्तूप बनेंगे। मतलब ग्रामीणों के लिए 12 करोड़ लीटर से भी अधिक पानी का इंतजाम हो जाएगा।

24 जनवरी को पुत्रदा एकादशी, जानें शुभ मुहूर्त

पौष मास में शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वालों की भगवान विष्णु सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। संतान प्राप्ति की कामना के लिए इस व्रत को उत्तम माना जाता है। इस साल पुत्रदा एकादशी 24 जनवरी 2021 को है।

शुभ मुहूर्त

व्रत प्रारंभः 23 जनवरी, शनिवार, रात 8:56 बजे।

व्रत समाप्तिः 24 जनवरी, रविवार, रात 10: 57 बजे।

पारण का समयः 25 जनवरी, सोमवार, सुबह 7:13 से 9:21 बजे तक।

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, संतान कामना के लिए इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह पति-पत्नी को साथ में भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीले फल, तुलसी, पीले पुष्प और पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप के बाद पति-पत्नी को साथ में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान श्रीकृष्ण को पंचामृत का भोग लगाना शुभ माना जाता है।

कथा

धार्मिक कथाओं के अनुसार, भद्रावती राज्य में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी शैव्या थी। राजा के पास सबकुछ था, सिर्फ संतान नहीं थी। ऐसे में राजा और रानी उदास और चिंतित रहा करते थे। राजा के मन में पिंडदान की चिंता सताने लगी। ऐसे में एक दिन राजा ने दुखी होकर अपने प्राण लेने का मन बना लिया, हालांकि पाप के डर से उसने यह विचार त्याग दिया। राजा का एक दिन मन राजपाठ में नहीं लग रहा था, जिसके कारण वह जंगल की ओर चला गया। राजा को जंगल में पक्षी और जानवर दिखाई दिए। राजा के मन में बुरे विचार आने लगे। इसके बाद राजा दुखी होकर एक तालाब किनारे बैठ गए। तालाब के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा आश्रम में गए और ऋषि मुनि राजा को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि राजन आप अपनी इच्छा बताए। राजा ने अपने मन की चिंता मुनियों को बताई। राजा की चिंता सुनकर मुनि ने कहा कि एक पुत्रदा एकादशी है। मुनियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने को कहा। राजा वे उसी दिन से इस व्रत को रखा और द्वादशी को इसका विधि-विधान से पारण किया। इसके फल स्वरूप रानी ने कुछ दिनों बाद गर्भ धारण किया और नौ माह बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई।

गणतंत्र दिवस ओर किसान कानून

✍नरेंद्र तिवारी 'एडवोकेट'
सेंधवा, 9425089251

गणतंत्र दिवस भारत की जनता के लिए ऐतिहासिक और राष्ट्रीय गौरव का दिवस है।इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था।गणतंत्र दिवस पर ही देश अपने संविधान से शासित होना शुरू हुआ था। भारत देश में दो प्रमुख राष्ट्रीय पर्व है।स्वंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस मसलन अंग्रजो से आजादी के बाद भी पूर्ण आजादी गणतंत्र दिवस को ही मिल पाई थी,जब भारत का संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस करीब है।ओर दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों के समर्थन में देश के लाखों किसान आंदोलन कर रहे है।इस आंदोलन को सात सप्ताह से अधिक का समय बीत गया है। केंद्र सरकार और किसान आंदोलनकारियों के मध्य अनेकों दौर की बैठके हो चुकी है।जिसका कोई भी नतीजा अब तक नही निकल पाया है। सरकार का कठोर रुख दिखाई दे रहा है,ओर किसान भी तीनो कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े हुए है। सरकार और किसान आंदोलनकारियों के बीच अगली बैठक 19 जनवरी को प्रस्तावित है। बैठक का यह दौर बेहद महत्वपूर्ण रहने की संभावना है।जिस पर सारे देश की निगाहें भी लगी हुई है।वह इसलिए कि किसानों संगठनों द्वारा तीनो कानूनों के रद्द किए जाने की मांग पूरी नही होने की दशा में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली कीसड़कों पर ट्रैक्टर परेड निकाले जाने की घोषणा की है।वैसे गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में किसानों की ट्रैक्टर परेड पर किसान नेताओं का कहना है कि यह परेड पूरी तरह अनुशासित होगी,जो भारत के गौरव को बढाने वाली होगी।

गणतंत्र दिवस को पूर्ण गौरव के साथ मनाने का प्रत्येक भारतीय को हक़ है,किसानों को भी यह हक प्राप्त है,कि वें अपने टैक्टरों पर तिरंगा लहराते हुए राष्ट्र की जयघोष करते हुए इस महत्वपूर्ण दिन जब देश के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं से सलामी ले रहे हो,तब देश के अन्नदाता भी इस अवसर के साक्षी बन सकें।

गणतंत्र दिवस पर भारत राष्ट्रीय रंग में रंगा हुआ रहता है।इस दिन देश की राजधानी दिल्ली में विशेष आयोजन होते है,जिसमे विदेशी मेहमान भी शामिल होते है। वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर होने वाला गरिमामय आयोजन जिसमे भारत की सैन्य शक्ति अपने शौर्य का प्रदर्शन करती है।विभिन्न प्रान्तों की झांकियां भारत की विविधता ओर एकता का सुंदर चित्र उकेरती है।राजधानी का यह आयोजन राष्ट्रीय गौरव ओर अभिमान का विषय होने से इसके इंतजाम काफी पूर्व से शुरू हो जाते है,इस कार्यक्रम में आमंत्रितों को विशेष पास जारी किया जाता है।जिससे आयोजन की व्यवस्था सुचारू बनी रहें तो क्या किसानों की टेक्टर परेड निकलने से गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के यातायात सहित अन्य व्यवस्थाएं प्रभावित होगी? जो गणतंत्र दिवस की गरिमा के अनुरूप नही होगा? क्या किसानों के इस प्रदर्शन से देश की राष्ट्रीय ख्याति प्रभावित होगी? यह सही है की देश के किसानों को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सडको पर ट्रैक्टर परेड निकालने का संवैधानिक अधिकार है,किन्तु किसानों का बड़ी संख्या में टैक्टरों के साथ दिल्ली में प्रवेश दिल्ली की व्यवस्थाओं को बिगाड़ सकता है,गणतंत्र दिवस पर ऐसी अप्रिय स्थितियों से बचा जाना चाहिए इससे पूर्व ही कोई निराकरण होना चाहिए।

गणतंत्र दिवस पर जब हम संविधान से शासित होने की शपथ लेते है तो हमे केंद्र द्वारा पारित तीनों किसान कानूनों को संवैधानिकता की कसौटी पर भी कसना होगा इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी कहना है कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है। उसमें कई ऐसे मुद्दे है जो संवैधानिक है।संविधान के तहत कृषि राज्य सरकार का विषय है और राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है,लेकिन इस मामले में केंद्र सरकार ने संसद के जरिए कानून बनाया है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनोती का विषय हो सकता है।क्योंकि यह संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है।

बेशक गणतंत्र में संविधान के शासन का महत्व है,जब देश का किसान अपने ऊपर लागू होने वाले कानूनों को लेकर सन्तुष्ट नही है,ओर कृषि के बारे में कानून बनाने का अधिकार राज्यो का है,तब केंद्र सरकार का सख्त रुख उचित नही जान पड़ता है। आशा की जाना चाहिए कि गणतंत्र दिवस के पूर्व सरकार और किसान बातचीत से इन समस्याओं का हल निकाल लेंगे,जो संविधान की विजय का प्रतीक होगा।न्याय पाने का हक किसानों को संविधान के द्वारा प्रदत्त है।

पानी की तस्वीर यहां लगायें नहीं होगी पैसों की कमी

वास्तु शास्त्र और फेंगशुई के अनुसार घर में चीजों के स्थान से घर के लोगों को बिजनेस में फायदा मिलता है और घर की आय कायम रहती है। लेकिन अगर घर में चीजे वास्तु के अनुसार नहीं है तो घर के सभी सदस्यों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेहनत करने के बावजूद भी पैसे नहीं टिकते हैं। अगर आपको पैसो की तंगी का सामना करना पड़ रहा है या घर में बरकत नहीं हो रही है तो हम यहां पर बताने जा रहे है फेंगशुई के अनुसार पानी का स्थान क्या है जिससे घर के लोगों को फायदे मिलेंगे और घर में बरकत बनी रहेगी।

■घर के लोगो की बरकत बनाये रखने के लिए पानी के शो पीस या तस्वीरें बालकनी में रखनी चाहिए। इससे घर में बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। घर के लोगो की बरकत बनी रहती है।■ पानी से भरे बर्तन को घर के पूर्व और उत्तर में रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर के लोगो का बुरा समय खत्म हो जाता है और हर काम में उनको सफलता प्राप्त होती है। ■ किचन में पानी से संबंधित चीजे रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। घर के लोगो की आय प्रभावित होती है। ■ किचन में पानी के शो पीस रखने से घर में कलह, लड़ाई, झगड़े बढ़ते है। ■ अगर आपके घर में गार्डन है और वाटरफाल लगा हुआ है, या लगवाना चाहते है तो ध्यान रहे वाटरफाल घर की दिशा में होना चाहिए। जिससे घर में सुख समृद्धि और बरकत बढ़ेगी। वाटरफाल का कभी भी घर के बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। ■ अगर आपके घर में फाउंटेन लगवा रहे है तो इसे घर के उत्तर, दक्षिण- पूर्व दिशा में लगवाए जिससे घर में गुडलक बना रहेगा और घर के लोगो की तरक्की होगी।

गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद होता है हकीक

तंत्र शास्त्र में कई प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि इनकी सहायता से कार्य जल्द ही पूर्ण हो जाते हैं। तन्त्र शास्त्र में प्रयोग किया जाने वाला ऐसा ही एक पत्थर है हकीक, इस पत्थर के पीछे यह भी मान्यता हैं कि जिसके घर में हकीक पत्थर होता है, उसके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होती। तंत्र शास्त्र में हकीक पत्थर का विशेष महत्व होता हैं, जिसका प्रयोग अलग-अलग टोटकों को सफल बनाने के लिए किया जाता हैं। यह एक शांति पूर्ण रत्न है जो लोगों की मुश्किल घड़ी में मदद करता है और उन्हें शांति प्रदान करता है। हकीक से आंतरिक शक्ति और मज़बूती प्राप्त होती है। यह तनाव पूर्ण परिस्थितियों में भी काफी मददगार साबित होता है। हकीक आपको व्यावहारिक निर्णय लेने वाली स्थितियों में शांत बनाए रखता है। हकीक दैविक ऊर्जा के साथ संपर्क बनाए रखने में मदद करता है। हकीक पत्थर को लक्ष्मी माता का प्रतिरूप भी माना जाता हैं। तंत्र शास्त्र के साथ-साथ हकीक पत्थर का प्रयोग पूजा-अर्चना तथा किसी भी देव की उपासना व साधना करने के लिए भी काफी किया जाता है। पत्थर से कई ऐसे चमत्कारी उपाय किया जा सकते हैं, जिससे दरिद्रता लोगों के आसपास भी नहीं फटकती। इसके अलावा जो लोग हकीक के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, उन्हें काले हकीक की माला के बारे में जरूर जानकारी होती है। यह एक ऐसी माला है जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कहते हैं काले हकीक के मोतियों की माला पहनने से मानसिक शांति मिलती है। इसके अलावा यह हमारी कार्य के प्रति एकाग्रता को बढ़ाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह रत्न अच्छा और फायदेमंद माना जाता है।

आईबीसी के संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया वैध, जानिए अब क्या है नई व्यवस्था!

नई दिल्ली। एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के 2020 के कानूनी संशोधन को वैध करार दिया है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि डिफॉल्ट करने वाले बिल्डर के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई के लिए कम से कम 100 बायर्स साथ में एनसीएलटी के सामने अर्जी दाखिल कर सकते हैं। नैशनल कंपनी लॉ बोर्ड के सामने कम से कम 100 बायर्स के साथ हों तभी अर्जी दाखिल हो सकती है। इस बावत किए गए कानूनी संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रोहिंटन नरीमन की अगुवाई वाली बेंच ने आईबीसी की धारा-3 और 10 के प्रावधान को वैध ठहराया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में किए गए संशोधन और कानूनी प्रावधान वैध हैं और संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं करता है। अदालत ने कहा कि ये प्रावधान संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। धारा-3 के तहत प्रावधान है कि इन्सॉल्वेंसी अर्जी तभी दाखिल हो सकती है जब बिल्डर के खिलाफ कम से कम 100 आवंटियों की अर्जी हो या फिर कुल अलॉटी का 10 फीसदी में जो संख्या कम हो। पहले के नियम के तहत एनसीएलटी में डिफॉल्ट करने वाले बिल्डर के खिलाफ एक बॉयर भी अर्जी दाखिल कर सकता था।

सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कानून में किए गए बदलाव को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता बायर्स का कहना था कि उक्त कानूनी संशोधन संविधान के अनुच्छेद-21 व 14 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट में बायर्स की ओर से दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बायर्स के डिफॉल्ट करने वाले बिल्डर के खिलाफ आईबीसी की धारा-7 के तहत दिवालियापन की कार्रवाई के लिए अर्जी दाखिल करने का अधिकार है और इस तरह से देखा जाए तो उक्त संशोधन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है।

मारुति सुजुकी ने जिम्नी का निर्यात शुरू किया

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता मारुति सुजुकी इंडिया ने बुधवार को कहा कि उसने भारत से अपनी कॉम्पैक्ट गाड़ी जिम्नी का निर्यात शुरू कर दिया है, और उसकी पितृ कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन भारत के एक वैश्विक निर्यात केंद्र बनाना चाहती है। मारुति सुजुकी इंडिया ने एक बयान में कहा कि 184 वाहनों की पहली खेप मुंद्रा बंदरगाह से कोलंबिया और पेरू जैसे लैटिन अमेरिकी देशों के लिए रवाना हुई। कंपनी ने बताया कि तीन दरवाजे सुजुकी जिम्नी को मध्य पूर्व और अफ्रीकी बाजारों में निर्यात किया जाएगा। साथ ही कंपनी की योजना इसे भारतीय बाजारों में पेश करने की भी है। कंपनी ने कहा, ''सुजुकी जिम्नी के लिए भारत को उत्पादन केंद्र बनाकर मारुति सुजुकी की वैश्विक विनिर्माण स्थिति का फायदा उठाना चाहती है। सुजुकी जापान की क्षमता के मुकाबले दुनिया भर में इस मॉडल की कहीं अधिक मांग है। भारतीय विनिर्माण इस वैश्विक मांग को पूरा किया जाएगा।'' इस बारे में मारुति सुजुकी इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ केनिची आयुकावा ने कहा कि जिम्नी का विनिर्माण मारुति सुजुकी के गुरुग्राम संयंत्र में किया जा रहा है और इसके साथ कंपनी के कुल निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

ई-वाणिज्य क्षेत्र में एफडीआई नियमों में बदलाव करेगी सरकार

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ई-वाणिज्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है जिनके तहत इस क्षेत्र की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) वाली ऐसी कंपनियों को उन विक्रेताओं से उत्पाद खरीदने से रोकना है जिनमें उनकी खुद अथवा उनकी मूल कंपनी की अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सरकार ने इससे पहले दिसंबर 2018 में उत्पादों की आनलाइन बिक्री के लिये मंच उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को उन कंपनियों के उत्पाद बेचने से रोका था जिनमें उनकी प्रत्यक्ष हिस्सेदारी है। मौजूदा नीति के मुताबिक आनलाइन बिक्री मंच उपलब्ध कराने वाली कंपनियों में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है लेकिन उनके लिये गोदामों में रखे तैयार माल की बिक्री करने जैसी गतिविधियां चलाने का निषेध है। सरकार का एफडीआई वाली ई-वाणिज्य कंपनियों के मामले में नियमों में बदलाव के बारे में विचार करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि देश के व्यापारियों का संगठन कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि ई- वाणिज्य कंपनियां फेमा और एफडीआई नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। कैट के मुताबिक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अमेजन और फ्लिपकार्ट द्वारा नियमों के कथित उल्लंघन संबंधी ज्ञापन को प्रवर्तन निदेशालय और रिजर्व बैंक को जरूरी कार्रवाई के लिये भेज दिया है।

नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु शीर्ष तीन में शामिल

नई दिल्ली। एजेंसी

नीति आयोग द्वारा बुधवार को जारी दूसरे नवाचार सूचकांक में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल को शीर्ष पांच राज्यों में स्थान मिला। आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत द्वारा जारी सूचकांक को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर विकसित किया गया है।

भारत नवाचार सूचकांक 2020 में ये राज्य रहे सबसे नीचे

सूचकांक में झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार का स्थान सबसे नीचे रहा। भारत नवाचार सूचकांक 2020 नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयासों तथा उनके सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्थान देता है। इस सूचकांक का मकसद नवचार के क्षेत्र में राज्यों की ताकत और कमजोरियों का पता लगाकर उन्हें इस दिशा में मजबूती लाने के लिए प्रेरित करना है। इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तुलना के लिहाज से 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा नौ शहरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है।

15 जनवरी तक 31 फीसदी बढ़ा चीनी उत्पादन, जानिए-अब तक कितना हुआ उत्पादन

नई दिल्ली। एजेंसी

देश का चीनी उत्पादन 15 जनवरी तक एक साल पहले की तुलना में 31 फीसदी बढ़कर 142.70 लाख टन हो गया। उद्योग निकाय इस्मा ने सोमवार को यह जानकारी दी। भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) ने अक्टूबर 2020 से शुरू चीनी विपणन वर्ष 2020-21 में चीनी उत्पादन 13 फीसदी बढ़कर 310 लाख टन रहने का अनुमान जताया है। पिछले वर्ष 274.2 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश भारत में 2019-20 विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के 15 जनवरी तक 108.94 लाख टन का हुआ था। इस्मा ने कहा कि चालू सत्र में 15 जनवरी तक चीनी उत्पादन 142.70 लाख टन रहा, जो पिछले साल से 33.76 लाख टन अधिक है। बता दें, पिछले साल के 440 मिलों की तुलना में इस बार 487 चीनी मिलों में पेराई शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन इस बार 15 जनवरी तक मामूली कमी के साथ 42.99 लाख टन रहा। राज्य में पिछले वर्ष की समानावधि में 43.78 लाख टन उत्पादन हुआ था। इसी दौरान महाराष्ट्र में उत्पादन एक साल पहले की समान अवधि में 25.51 लाख टन के मुकाबले इस बार बढ़कर 51.55 लाख टन हो गया। तीसरे सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कर्नाटक में 29.80 लाख टन उत्पादन हुआ है, जो एक साल पहले समानावधि में 21.90 लाख टन था। इस्मा ने एक बयान में कहा कि गुजरात में चीनी उत्पादन 4.40 लाख टन, तमिलनाडु में 1.15 लाख टन तक पहुंच गया, जबकि शेष राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा ने मिलकर इस साल के 15 जनवरी तक 12.81 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है। एथेनॉल के बारे में इस्मा ने कहा कि तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) ने विपणन वर्ष 2020-21 के लिए लगभग 309.81 करोड़ लीटर का आवंटन किया है, जिसमें क्षतिग्रस्त अनाज और अधिशेष चावल से लगभग 39.36 करोड़ लीटर भी शामिल है। विपणन वर्ष 2019-20 के दौरान चीनी मिलों को आवंटित अधिकतम स्वीकार्य निर्यात कोटा (एमएईक्यू) के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर 2020 के दौरान लगभग तीन लाख टन चीनी का निर्यात किया गया, जिसे दिसंबर 2020 तक बढ़ाया गया था।

भारत ने निभाया पड़ोसी धर्म

सबसे पहले भूटान को गिफ्ट में भेजी 1.5 लाख कोरोना वैक्सीन

मुंबई। एजेंसी

संकट का साथी भारत कोरोना काल में भी अपने पड़ोसी देशों की मदद करने से पीछे नहीं हट रहा है। आज से भारत सरकार ने भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स को अनुदान सहायता के तहत (गिफ्ट के तौर पर) कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति शुरू कर दी है। भारत की तरफ से सबसे पहले भूटान को गिफ्ट के तौर पर आज सुबह कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के 1.5 लाख डोज भेजे गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की यह कोविशील्ड वैक्सीन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बुधवार सुबह भूटान के थिम्पू के लिए रवाना हुई। आज किसी भी वक्त वैक्सीन की यह पहली खेप भूटान पहुंच जाएगी। बता दें कि भारत ने अपनी जरूरतों को देखते हुए पड़ोसी देशों के लिए बड़ा दिल दिखाया है और आज से पड़ोसी देशों को वैक्सीन की डिलीवरी शुरू कर दी है।

भारत की तरफ से गिफ्ट के तौर पर कोरोना वैक्सीन पाने वाला भूटान पहला पड़ोसी देश बन गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कोविशील्ड वैक्सीन की 1.5 लाख डोज की पहली खेप भारत ने भूटान को रवाना की। भूटान के अलावा, अन्य पड़ोसी देशों को इसी तरह आज अलग-अलग समय पर भारत सरकार वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार को पड़ोसी और प्रमुख भागीदार देशों से भारत निर्मित टीकों की आपूर्ति के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन अनुरोधों के जवाब में आपूर्ति सुनिश्चित करने का फैसला किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरीशस के संबंध में आवश्यक नियामक मंजूरी की प्रतीक्षा है।

मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और अन्य को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से भारत में टीकाकरण कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, चरणबद्ध रोलआउट की घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत आने वाले हफ्तों और महीनों में चरणबद्ध तरीके से कोविड टीकों की आपूर्ति जारी रखेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि घरेलू निर्माताओं के पास विदेश में आपूर्ति करते समय घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक होगा।

भारत और भूटान के बीच खास रिश्ते के मद्देनजर भारत ने कोरोना काल में भी कोविड-19 प्रतिबंधों के बावजूद हर जरूरी सामान की सप्लाई को सुनिश्चित किया था। भारत ने भूटान को अब तक करीब 2.8 करोड़ रुपये से अधिक की कीमत की जरूरी दवाइयां, मेडिकल सप्लाई, पारासिटामोल, हाइड्रोक्सीक्लोक्वीन, पीपीई किट, एन-95 मास्क, एक्स-रे मशीनें और टेस्ट किट मुहैया कराए हैं। इतना ही नहीं, कोरोना काल में भारत ने भूटान के साथ एक ट्रांसपोर्ट बबल समझौता भी किया था ताकि दोनों देशों के बीच सुरक्षित हवाई यात्रा को सुनिश्चित किया जा सके।

इतना ही नहीं, भारत ने भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे 2,000 से अधिक भूटानी नागरिकों को उनके घर तक पहुंचाया था। सूत्रों ने कहा कि भारत ने वंदे भारत मिशन के तहत तीसरे देशों में फंसे 14 भूटानी नागरिकों को भारत वापस लाया था और फिर भूटान उनके घर पहुंचाया था। भारत ने भूटान सरकार के अनुरोध पर कोरोना काल में व्यापार और पारगमन को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें टर्शा टी गार्डन (भारत) और अहले (भूटान) के माध्यम से एक नया व्यापार मार्ग खोलना शामिल है। सूत्रों के मुताबिक, नागराकाटा, अगरतला और पांडु और जोगीघोपा नदी के नए बंदरगाह जल्द ही चालू होंगे।

देश का निर्यात दिसंबर में दो महीने बाद बढ़कर 27.15 अरब डॉलर पर, व्यापार घाटा भी बढ़ा

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश का निर्यात दिसंबर, 2020 में मामूली बढ़कर 27.15 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस दौरान आयात 7.56 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 42.59 अरब डॉलर रहा। इस तरह व्यापार घाटा बढ़कर 15.44 अरब डॉलर पर पहुंच गया। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। दिसंबर, 2019 में देश का वस्तुओं का निर्यात 27.11 अरब डॉलर और आयात 39.59 अरब डॉलर रहा था। समीक्षाधीन महीने में सोने का आयात 81.82 प्रतिशत बढ़कर 4.48 अरब डॉलर पर पहुंच गया। आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर, 2020 में व्यापार घाटा 15.44 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। इससे पिछले साल के समान महीने में यह 12.49 अरब डॉलर रहा था। इस तरह व्यापार घाटा 23.66 प्रतिशत बढ़ा है। इससे पहले अक्टूबर और नवंबर में निर्यात में गिरावट आई थी। इस तरह निर्यात में दो महीने बाद वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर में पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 35.35 प्रतिशत घटकर 2.34 अरब डॉलर रह गया। वहीं सिलेसिलाए परिधानों का निर्यात 15.05 प्रतिशत घटकर 1.19 अरब डॉलर रह गया। हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का निर्यात 16.51 प्रतिशत बढ़कर 1.25 अरब डॉलर पर और रसायन का 10.79 प्रतिशत बढ़कर दो अरब डॉलर पर पहुंच गया। इसी तरह दिसंबर, 2020 में चावल, चाय, मसालों और खली के निर्यात में बढ़ोतरी हुई। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर की अवधि में देश का निर्यात 15.73 प्रतिशत की गिरावट के साथ 200.80 अरब डॉलर रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 238.27 अरब डॉलर रहा था। आयात की बात की जाए, तो दिसंबर में कच्चे तेल का आयात 10.61 प्रतिशत घटकर 9.58 अरब डॉलर रहा। दिसंबर, 2019 में यह 10.72 अरब डॉलर रहा था। चालू वित्त वर्ष के पहले नौ माह अप्रैल-दिसंबर में तेल आयात 44.49 प्रतिशत घटकर 53.69 अरब डॉलर रहा। दिसंबर, 2020 में गैर-तेल आयात 33 अरब डॉलर रहा, जो दिसंबर, 2019 की तुलना में 14.30 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल-दिसंबर में गैर-तेल आयात 23.51 प्रतिशत घटकर 204.58 अरब डॉलर रह गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 267.47 अरब डॉलर रहा था। यदि वस्तुओं और सेवाओं दोनों की बात की जाए, तो देश का कुल निर्यात अप्रैल-दिसंबर में 12.65 प्रतिशत घटकर 348.49 अरब डॉलर रहा। अप्रैल-दिसंबर में कुल आयात भी सालाना आधार पर 25.86 प्रतिशत घटकर 343.27 अरब डॉलर पर आ गया। निर्यातकों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) के अध्यक्ष शरद कुमार सर्राफ ने कहा कि मासिक निर्यात सकारात्मक हो गया है। ज्यादातर उत्पादों के निर्यात में उम्मीद के अनुरूप सुधार हुआ है। इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद (ईईपीसी इंडिया) ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मांग सुस्त है। इससे निर्यातकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

एक सप्ताह में रिकार्ड 534 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआः सरकार

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सड़क परिवहन मंत्रालय ने रविवार को कहा कि गत आठ जनवरी से शुरू हुये सप्ताह में रिकार्ड 534 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने पिछले आठ जनवरी से शुरू हुये सप्ताह में 534 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर एक रिकार्ड कायम किया है। बयान में कहा गया है कि मंत्रालय ने अप्रैल 2020 से लेकर 15 जनवरी 2021 की अवधि में 8,169 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया। इस लिहाज से प्रतिदिन 28.16 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया। वहीं पिछले साल इसी अवधि में 7,573 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। तब प्रतिदिन 26.11 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ। मंत्रालय को उम्मीद है कि निर्माण की इस गति के साथ वह 31 मार्च 2021 तक 11 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण के लक्ष्य को पार कर लेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 2020 से 15 जनवरी 2021 की अवधि में उसने 7,597 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का ठेका दिया जबकि 2019- 20 में इसी अवधि में 3,474 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं का ठेका दिया गया था। इस प्रकार परियोजनाओं के निर्माण का ठेका देने की गति भी इस साल दोगुने से अधिक हो गई। मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2019- 20 में कुल मिलाकर 8,948 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं के निर्माण का ठेका दिया गया जबकि 10,237 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। बयान में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष के शुरुआती दो माह में कोरोना वायरस महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू होने के बावजूद सड़क निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय गति हासिल की गई है।

यात्रियों पर निगाह के लिए दिल्ली हवाईअड्डे पर कंप्यूटर विजन प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन

नयी दिल्ली। एजेंसी

दिल्ली हवाईअड्डे पर यात्रियों को ट्रैक करने, प्रतीक्षा समय कम करने और अपने टर्मिनलों पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिये 'कंप्यूटर विजन' तकनीक का मूल्यांकन किया जा रहा है। एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को यह कहा।

कंप्यूटर विजन प्रौद्योगिकी हवाईअड्डे पर यात्री घनत्व का विश्लेषण और समझने के लिये तस्वीरों का उपयोग करती है। इसे जीएमआर समूह के हैदराबाद हवाईअड्डे पर पहले ही स्थापित किया जा चुका है। दिल्ली हवाईअड्डा भी जीएमआर समूह के नियंत्रण में है। दिल्ली हवाईअड्डे ने पिछले महीने टर्मिनल तीन पर 'शोविस' यात्री ट्रैकिंग सिस्टम लगाया था। यह यात्री घनत्व की जांच करने के लिये सेंसर का उपयोग करता है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विदेह कुमार जयपुरियार ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "हम कुछ अन्य तकनीकों का भी मूल्यांकन कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि टर्मिनल एक को नये सिरे से तैयार किया जा रहा है, चूंकि शोविस प्रणाली परखी हुई है, एक कंप्यूटर विजन प्रौद्योगिकी भी है, जिसका हैदराबाद हवाईअड्डे ने परीक्षण किया है।"

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।